

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 008/2025(रा.प्रा.प.) (GCMS 2025/8)	दायर दिनांक 17.02.2025	निर्णय दिनांक 08.10.2025
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

1. जगदीश पिता जोधराज जाति भील आयु वयस्क निवासी लूणखन्दा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती देवली जगदीश जाति भील आयु वयस्क निवासी लूणखन्दा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)
अनुपस्थित

प्रार्थी
विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी भू-आवंटन कमेटी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 191/2021 दिनांक 03.11.2021

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा ने एक प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार की और से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण को मौजा लूणखन्दा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 1186 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म भूमि भटवेड के संबंध में भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षीगण का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काशत नहीं रहा है। विपक्षीगण का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 11.03.2025, 08.04.2025, 30.04.2025, 30.07.2025, 06.08.2025 व 20.08.2025 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये एवं न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया। दिनांक 08.10.2025 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की



अनुपस्थिति रिकार्ड की गई है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल अभिलेख पत्रावली प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/अभिलेखागार/2025/832 दिनांक 11.03.2025 से प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली एक तरफा सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को मौजा लूणखन्दा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 1186 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म भूमि भटवेड के संबंध में भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षीगण का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काशत नहीं रहा है। विपक्षीगण के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण किसी भी स्थिति में आवंटन के पात्र नहीं है।

विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान लूणखन्दा को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच-पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईशतदुआ से साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]



Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 के हस्ताक्षर ही अंकित है अप्रार्थी संख्या 02 के हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित नहीं है। इसके साथ ही अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप-कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कब्जा रहा हो। इसके साथ ही प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में श्री गोपाल लाल जीनगर, तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपना अखण्डित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों के प्रति-उत्तर में विपक्षी पक्ष द्वारा काउन्टर शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटिती का कब्जा नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप-2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटिती को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 1186 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 01 व 02 को आवंटित 0.43 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रकरण में बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। जिससे आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस



दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है।

इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रकरण में बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। जिससे आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 191/2021 दिनांक 03.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है, एवं विपक्षीगण को किया गया आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा लूणखन्दा पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 13.02.2022 को निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 191/2021 दिनांक 03.11.2021 का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा लूणखन्दा पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 13.02.2022 निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 191/2021 दिनांक 03.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

